हिन्दी सान्ध्य दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष : 01 अंक : 280 : जौनपुर, बुधवार 12 जुलाई 2023 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज – 4 मूल्य : 2 रूपया

पेड़ लगाओ–पेड़ बचाओ के संदेश के साथ प्रदेश मनाएगा वन महोत्सव : योगी

एजेन्सी

लखनऊ। प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा वाले उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव अब जनांदोलन का स्वरूप ले चुका है। विगत 06 वर्षों में 131 करोड़ से अधिक पौधरोपण किया जा चुका है। इस कार्य में व्यापक जनसहयोग प्राप्त हुआ है। वर्ष 2017–18 में 5.72 करोड़, 2018–19 में 11.77 करोड़, 2019–20 में 22.60 करोड़, 2020–21 में 25.87 करोड़, 2021–22 में 30.53 करोड़ और 2022–23 में 35.49 करोड़ पौधे लगाए गए। यह सुखद है कि पौधे लगाने के साथ–साथ इनके संरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है।विगत 01 से 07 जुलाई तक आयोजित जागरूकता सप्ताह के दौरान आम जन में बड़ा उत्साह देखा गया। यह उत्साह इस वर्ष के वन महोत्सव को सफल बनाने का आधार बनेगा। आमजन की अधिकाधिक सहभागिता से ही हरित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। विद्यालयों में प्रभात फेरी, स्लोगन, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता, दीवार लेखन जैसे कार्यक्रम सतत जारी रखे जाने चाहिए। प्रदेश में वर्षाकाल

प्रारंभ हो चुका है। यह मौसम पौधरोपण के लिए आदर्श समय है। जागरूकता सप्ताह के सफल आयोजन के बाद अब हम 22 जुलाई को श्वन महोत्सवश के रूप में वृहद पौधरोपण के कार्यक्रम से जुड़ना होगा। भरपूर उत्साह, उमंग के साथ विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पौधरोपण का नवीन रिकॉर्ड बनाने को तैयार हैं।

इस वर्ष वृहद पौधरोपण अभियान में 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य लेकर हर विभाग, हर संस्थान हर नागरिक को प्रयास करना होगा। वन विभाग द्वारा विभागवार पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। मंडलवार लक्ष्य भी तय किए गए हैं। हर गांव में कम से कम 01 हजार पौधे लगाने का प्रयास हो। 15 अगस्त के दिन एक साथ 05 करोड़ पौधे लगाए जाने की तैयारी करें। पौधरोपण के लिए वन भूमि, ग्राम पंचायत एवं सामुदायिक भूमि, एक्सप्रेस–वे, हाई–वे 04 लेन सड़क, नहर, विकास प्राधिकरणों की भूमि, रेलवे की भूमि, चिकित्सा संस्थान, शिक्षण संस्थान की भूमि के साथ–साथ, नागरिकों द्वारा निजी परिसरों का उपयोग किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के मैदान के चारों ओर पौधारोपण किया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर न्यूनतम 01 हजार पौधे लगाए जाएं। शहरी वार्डों में भी पौधारोपण के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। गोशालाओं में पौधरोपण कराएं, साथ ही पौधे की सुरक्षा के लिए ट्री–गॉर्ड भी लगवाएं। निजी क्षेत्रों, एनजीओ, धार्मिक,सामाजिक संस्थाओं को जोड़ें। वृहद पौधरोपण अभियान की सफलता के लिए पौधों की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा समय से सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए जाएं। हाईटेक नर्सरी तैयार करें। हर किसी को उच्च गुणवत्ता के पौधे सुलभता से मिल सके, इसके लिए विधिवत तैयारी और प्रचार–प्रसार किया जाए। पौधरोपण स्थलों की जियो टैगिंग की जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत निजी खेत की मेड़ पर पौधारोपण को प्रोत्साहित करते हुए 'मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन' योजना के रूप में किसान और पर्यावरण के हित में अत्यंत उपयोगी योजना संचालित है। इस योजना अंतर्गत मनरेगा के लाभार्थी यदि अपनी भूमि पर यदि न्यूनतम 200 पौधे लगाकर उनका संरक्षण करता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष में 50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था है।

अनुच्छेद 370 पर 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

एजेन्सी

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह पूर्ववर्ती जम्मू–कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दो अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कई प्रक्रियागत निर्देश पारित करते हुए विभिन्न पक्षों द्वारा लिखित प्रतिवेदन और अन्य लिखित दलीलें देने की समय सीमा 27 जुलाई तय की। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने कहा कि याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर रोजाना आधार पर होगी। सोमवार और शुक्रवार को शीर्ष अदालत में विविध मामलों पर सुनवाई की जाती है। पीठ ने लिखित दलीलें तैयार करने और इसे 27 जुलाई से पहले दाखिल करने के लिए 2 वकीलों को नियुक्त किया है, जिसमें से एक वकील याचिकाकर्ता की ओर से और एक सरकार की ओर से है।

साथ ही पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि 27 जुलाई के बाद कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। पीठ ने कहा कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू–कश्मीर में 5 अगस्त 2019 की अधिसूचना के बाद प्रचलित स्थितियों के संबंध में केंद्र की ओर से सोमवार को दाखिल हलफनामे का पांच–न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा संवैधानिक मुद्दे पर की जा रही सुनवाई पर कोई असर नहीं होगा। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने बताया कि दो याचिकाकर्ताओं आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारी शाह फैसल और कार्यकर्ता शेहला राशिद शोरा ने याचिकाकर्ताओं की सूची से अपना नाम वापस लेने के लिए एक आवेदन दिया है। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई याचिकाकर्ताओं की सूची से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद पीठ ने शाह और शेरा को याचिकाकर्ताओं की सूची से अपना नाम वापस लेने की अनुमति दे दी। केंद्र ने पांच अगस्त 2019 को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू–कश्मीर का विशेष दर्जा निरस्त कर दिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में विभाजित कर दिया था।

सोशल मीडिया, कांग्रेस ने बीजेपी को उसी के खेल में दी पटखनी

एजेन्सी

नयी दिल्ली। 2024 के लोकसभा चुनावों में एक साल से भी कम समय बचा है, ऐसे में कांग्रेस ने लोगों तक पहुंचने के लिए अपने सोशल मीडिया को सक्रिय कर दिया है। पिछले एक साल में देश की सबसे पुरानी पार्टी पहुंच के मामले में तकनीक प्रेमी भाजपा को मात देने में सफल रही है। पार्टी नेताओं के मुताबिक, पत्रकार से नेता बनीं सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने पिछले साल 22 जून को सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म विभाग की कमान संभाली थी, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी के रुख में जबरदस्त बदलाव लाया है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि श्रीनेत के नेतृत्व में सोशल मीडिया टीम ने पिछले साल जबरदस्त काम किया और वह सत्तारूढ़ भाजपा को हराने में सफल रही, जो ऑनलाइन अभियानों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए जानी जाती है। पार्टी नेता ने कहा कि फेसबुक पर कांग्रेस की पहुंच पिछले साल जुलाई में 13.78 मिलियन थी, जो मई 2023 में 15.47 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 15.91 मिलियन हो गई। इसी तरह, यूट्यूब पर पार्टी को 21.56 मिलियन व्यूज मिलते थे, जो मई 2023 में 139.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 51. 71 मिलियन व्यूज हो गए। पार्टी नेता ने कहा कि श्रीनेत के नेतृत्व में कांग्रेस ने इंस्टाग्राम पर व्यापक छाप छोड़ी है, जो युवाओं को जोड़ने के लिए जाना जाता है। पार्टी नेता ने कहा कि पिछले साल जुलाई में इंस्टाग्राम पर एंगेजमेंट 1.45 मिलियन थी, जबकि मई 2023 में यह 1,290.4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए अब 20.2 मिलियन तक पहुंच गई है।

ट्विटर पर भी कांग्रेस अपने आकर्षक पोस्ट से खास छाप छोड़ने में कामयाब रही है। पार्टी नेता ने कहा, "पिछले साल जुलाई में ट्विटर पर कांग्रेस का इंप्रेशन 48.3 मिलियन था, जबकि इस साल मई में यह 242.93 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 165.8 मिलियन इंप्रेशन तक पहुंच गया। पार्टी नेता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कांग्रेस की व्यस्तता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी रही है कि वह अपने पोस्ट की पहुंच और लोगों से जुड़ाव के मामले में भाजपा को बहुत पीछे छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस साल 5 जून से 2 जुलाई के बीच, कांग्रेस ने अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल पर 560 सामग्री साझा की, इसके 6.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसे 20.2 हजार नए पेज लाइक मिले, जबकि भाजपा, जिसके आधिकारिक फेसबुक पेज पर 16 मिलियन पेज लाइक हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर 500 सामग्री पोस्ट करने के बावजूद केवल 2.2 हजार लोगों द्वारा एक पेज लाइक प्राप्त किया गया।

महंत नरेंद्र गिरी मौत का असली आरोपी पुलिस की पहुंच से बाहर

एजेन्सी

प्रयागराज। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि मौत मामले में अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस मामले में दोबारा जांच कराने जाने की मांग की है। महंत हरि गिरी ने कहा है कि महंत नरेंद्र गिरी एक संघर्षशील व्यक्ति थे, वह आत्महत्या नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि वह स्टूल पर चढ़ नही सकते थे। उनके घुटने में भी समस्या थी जिसके चलते वह स्टूल पर चढ़कर फांसी का फंदा गले में नहीं लगा सकते थे। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से हम कह रहे हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते थे। महंत हरि गिरी ने नरेंद्र गिरि की खुदकुशी मामले की जांच नए सिरे कराए जाने की मांग की है। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी श्री मठ बाघम्बरी गद्दी में 20 सितंबर 2021 को फांसी के फंदे से लटके पाए गए थे।

मिशन चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग में पीएम मोदी होंगे शामिल

एजेन्सी

नयी दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अधिक ईंधन एवं कई सुरक्षित उपायों से लैस 'चंद्रयान–3 का शुक्रवार (14 जुलाई) को प्रक्षेपण करने के साथ चंद्रमा पर उतरने का एक और प्रयास करने को तैयार है। इसके लिए चांद पर एक बड़ा 'लैंडिंग स्थल निर्दिष्ट किया गया है। इसरो ने कहा कि इस बार इसने विफलता–आधारित डिजाइन का विकल्प चुना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुछ चीजें गलत होने पर भी लैंडर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर सके। चंद्रयान–3 शुक्रवार को दोपहर 2. 35 बजे चंद्रमा के लिए उड़ान भरने को तैयार है। मिशन 'चंद्रयान–3 की लॉन्चिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या शामिल होंगे, इस सवाल के जवाब में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि उन्हें लॉन्चिंग के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन फिलहाल यह कंफर्म नहीं है कि वह इस मौके पर मौजूद रहेंगे या नहीं। एक न्यूज चौनल को इंटरव्यू देते हुए इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा कि प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी उच्च अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, अब वे चंद्रयान–3 मिशन की लॉन्चिंग में शामिल होंगे या नहीं हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल यह निश्चित नहीं है कि पीएम मोदी मिशन की लॉन्चिंग में शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले साल 2019 में चंद्रयान–2 मिशन के लॉन्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। 22 जुलाई, 2019 को लॉन्च किया गया चंद्रयान–2 सफल नहीं हो सका था और चांद पर लैंड करते ही वह क्रैश कर गया था। उस समय के. सिवान इसरो के अध्यक्ष थे और मिशन के फेल होने पर वे भावुक होकर रो पड़े थे, उस समय प्रधानमंत्री ने उन्हें संभाला और हौसला बढ़ाया था। 14 जुलाई को दोपहर 2.35 बजे चंद्रयान–3 मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के बाद 45 दिनों तक यान अंतरिक्ष में रहेगा। इसरो चंद्रयान–3 को एलवीएम–3 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजेगा। सोमनाथ ने कहा कि हमने बहुत सी विफलताओं को देखा– सेंसर की विफलता, इंजन की विफलता, एल्गोरिदम की विफलता, गणना की विफलता। इसलिए, जो भी विफलता हो, हम चाहते हैं कि यह आवश्यक वेग और निर्दिष्ट मान पर उतरे। इसलिए, अंदर अलग–अलग विफलता परिदृश्यों की गणना और योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया है।

लाड़ली बहना के फिर भरे जाएंगे 25 जुलाई से आवेदन : शिवराज

एजेन्सी

इंदौर। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए शुरु की गई लाडली बहना योजना में बनी दो बाधाओं को दूर करने के चलते पात्रता की श्रेणी में लाखों महिलाएं आ गई हैं। लिहाजा, वो आगामी 25 जुलाई से अपने आवेदन भर सकेंगे। यह ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में लाडली बहनों की प्रदेश स्तरीय विशाल सम्मेलन में योजना की दूसरी किश्त अंतरित करते हुए किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सप्त क्रांति के माध्यम से प्रदेश में महिलाओं एवं बेटियों के मान–स्वाभिमान को बढ़ाने, जीवन की सुरक्षा, सशक्त बनाने, कल्याण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में मदद देने और आजीविका के साधन तथा अवसर उपलब्ध कराने के कार्य तेजी से किये जा रहे हैं। महिलाओं एवं बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की पहल की जा रही है। यह एक सामाजिक क्रांति है। इस क्रांति के माध्यम से महिलाओं एवं बेटियों को नया जीवन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में दस तारीख का दिन अब ऐतिहासिक हो गया है। यह दिन बहनों के सम्मान, शान, स्वाभिमान, स्वावलंबन तथा सामाजिक क्रांति का दिन बन गया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में मिल रही राशि को धीरे–धीरे बढ़ाकर तीन हजार रूपये प्रतिमाह तक किया जाएगा। साथ ही महिलाओं को आजीविका मिशन में अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आमदनी हर माह दस हजार रूपये तक की जायेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना में अब वैवाहिक पात्र महिलाओं की न्यूनतम आयु 23 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष की गई है।

बाराबंकी में बदमाशों ने सिपाही पर चाकू से हमला किया, तीन गिरफ्तार

एजेन्सी

बाराबंकी। जिले के जैदपुर कस्बे में जांच–पड़ताल के लिए निकली पुलिस की अपराध शाखा की टीम में शामिल एक सिपाही को कथित तौर पर क्वालिस सवार पांच बदमाशों ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनमें दो को पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि अपराध शाखा की टीम सोमवार की रात जैदपुर थाना क्षेत्र के कस्बे में एक मामले की छानबीन के लिए निकली हुई थी। टीम जब कस्बे में घूम रही थी, इसी दौरान उन्हें एक अज्ञात क्वालिस गाड़ी खड़ी दिखाई दी। टीम उस गाड़ी के पास गई और सिपाही अंकित तोमर ने उन लोगों से पूछताछ करना चाहा। पुलिस ने बताया कि आरोपी जैदपुर क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन का तार काट रहे थे, इसी दौरान टीम ने इन्हें रोकना चाहा, जिसके बाद इन्होंने सिपाही अंकित तोमर पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। सिपाही को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।पुलिस ने बताया कि घटना के बाद अपराध शाखा की टीम ने भाग रहे बदमाशों का पीछा कर उन्हें घेर लिया। पुलिस से घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें दो आरोपियों को गोली लगी। पुलिस ने बताया कि बाद में क्वालिस चालक सहित तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया और घायल दोनों आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया जबकि दो अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक वाहन, दो देसी तमंचा व कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि घायल आरोपियों की पहचान रामजी यादव और जय मुकर्रर के रूप में हुई है, जो लखनऊ जिले के मोहनलालगंज और निगोहा के रहने वाले हैं। इन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। सिंह ने बताया कि वाहन चालक की पहचान गोंडा जिले के कोडारी थाना निवासी सुंदरलाल के तौर पर की गई है।

अमरनाथ यात्रा पर निकले भोले बाबा के बड़े भक्त दो अमेरिकी नागरिक, कहा, यहां आना सपने जैसा

एजेन्सी

जम्मू। अमरनाथ यात्रा केवल देश में ही नहीं ब्लकि विदेशियों पर भी कितना प्रबाव डालती है इसका एक ताजा वीडियो देखने को मिला। दरअसल, कैलिफोर्निया से आए दो अमेरिकी नागरिक जम्मू–कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर निकले। उन्होंने अपने इस यात्रा के अनुभव के बारे में बताया कि...स्वामी विवेकानन्द अमरनाथ आये, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। मैं इस कहानी को 40 वर्षों से जानता हूं..यहां आना असंभव लग रहा था और एक सपना था। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ हो गया एक साथ और हम यहां हैं... हम बता नहीं सकते कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं...बता दें कि जम्मू–श्रीनगर राजमार्ग के बंद होने के कारण स्थगित की गयी अमरनाथ यात्रा तीन दिन बाद मंगलवार अपराह्न स्थानीय आधार शिविर से फिर से शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रामबन खंड पर मरम्मत कार्य को लेकर राजमार्ग बंद कर दिया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण राजमार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे मरम्मत के बाद खोल दिया गया है।

उन्होंने बताया कि तीर्थयात्रियों के एक नये जत्थे को अमरनाथ गुफा मंदिर की आगे की यात्रा के लिए कश्मीर की ओर जाने की अनुमति दे दी गई है। तीर्थयात्री प्रतिदिन अमूमन तड़के 3.45 से 4.30 बजे के बीच जम्मू से रवाना होते हैं।यात्रा स्थगित होने के कारण करीब 15 हजार श्रद्धालु जम्मू और अन्य स्थानों पर फंसे हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि काजीगुंड में फंसे लोगों को भी जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी गई। यात्रा स्थगित होने के कारण लगभग आठ हजार तीर्थयात्री जम्मू, खासकर भगवतीनगर आधार शिविर में ही फंसे थे। इसी तरह, रामबन जिले के चंद्रकोट आधार शिविर में लगभग छह हजार तथा कठुआ और सांबा के शिविरों में लगभग दो हजार तीर्थयात्री फंसे हुए थे। हिमालयी क्षेत्र में स्थित 3,888 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर की 62–दिवसीय वार्षिक तीर्थयात्रा एक जुलाई को शुरू हुई, जो 31 अगस्त तक चलेगी। जम्मू आधार शिविर से 30 जून तक सात जत्थों में कुल 43,833 तीर्थयात्री गुफा मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं।

बिहार में शिक्षक बनाएंगे ऑनलाइन हाजरी, व्हाट्सएप चौटिंग पर भी रोक

एजेन्सी

पटना। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत शिक्षकों की अनुपस्थिति और उनकी लेटलतीफी पर अंकुश लगाए जाने को लेकर खास उपाय किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में जब से अपर मुख्य सचिव के रूप में तेजतर्रार आईएएस अधिकारी केके पाठक पदस्थापित हुए है, तब से विभाग को कार्यशैली में लगातार सुधार करने की कवायद की जा रही है।

इसके तहत शिक्षकों को जहां अब ऑनलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी वही अब वे स्कूल के समय व्हाट्सएप चौटिंग और रील्स नहीं देख सकेंगे। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि स्कूलों के निरीक्षण के बाद अब शिक्षकों और छात्र–छात्राओं की हाजिरी ऑनलाइन तरीके से करने की तैयारी की जा रही है। इसकी शुरूआत राजधानी पटना से 16 जुलाई से हो रही है।

सोना तो हो गया सस्ता, चांदी की बढी कीमत

एजेन्सी

नयी दिल्ली सोने की कीमतों में आज भी गिरावट देखी जा रही है। सोने के भाव लगातार 58 हजार रुपए के करीब बने हुए हैं। कल भी सोने के भाव में गिरावट देखी गई थी।

लखीमपुर खीरी हिंसा, आशीष की जमानत 26 सितंबर तक बढ़ाई

एजेन्सी

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष की अंतरिम जमानत मंगलवार को 26 सितंबर तक बढ़ा दी। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा 2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी हैं। लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान तीन अक्तूबर 2021 को हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। यूपी पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था और इसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना के बाद एसयूवी के चालक और भाजपा के दो कार्यकर्ताओं को गुस्साए किसानों ने कथित रूप से पीट–पीटकर मार डाला था। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।

यमुना का तटबंध टूटा, 40000 एकड़ फसल पानी में डूबी

एजेन्सी

पानीपत। पानीपत में सनौली खुर्द खंड के गांव नवादा पार व तामशाबाद के बीच देर रात को यमुना का तटबंध टूट गया। जिससे खंड के पांच गांव नवादा पार, जलालपुर द्वितीय, पत्थरगढ़, राणा माजरा व गढी बेसक का संपर्क कट गया है।

सम्पादकीय

तबाही की बारिश

उत्तर भारत समेत देश के अन्य भागों में अप्रत्याशित रूप से लगातार होती बारिश ने हा–हाकार मचाया है। बरसात के मौसम में बारिश और जलधाराओं में उफान आना सामान्य बात है। लेकिन इस बार की अतिवृष्टि ने बताया है कि मनुष्य शक्तिशाली होने का भले ही दंभ भरता रहे लेकिन कुदरत के रौद्र के सामने वह बौना ही है। जगह–जगह बादल फटने, नदियों में बाढ़, पानी रोकने में नाकाम बांध और भूस्खलन की घटनाओं ने लोगों में भय पैदा किया है। देश का जनजीवन अस्त–व्यस्त हुआ है। पुलों के टूटने, बस्तियों में नौका चलाने, मकानों के भरभरा कर गिरने व कारों के बहने के वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को दहशत से भर रहे हैं। कारोबार ठप हैं, स्कूल–कालेज बंद कर दिये गये हैं। फिर भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। कई राज्यों में रेड, ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचाया है। करीब तीन–चार हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान लगाया गया है। हिमाचल में बाढ़, बादल फटने, जलधाराओं में उफान व भूस्खलन में सत्रह लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। जलधाराओं में उफान से नदियों के किनारे स्थित सड़कों, मकानों, होटलों व हाईवे को नुकसान पहुंचना स्वाभाविक है। हिमाचल व उत्तराखंड में सैकड़ों सड़कें तबाह हुई हैं। विद्युत व्यवस्था ठप होने और यातायात बाधित होने की भी खबरें हैं। हिमाचल में रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब आदि नदियों में उफान से संकट गहरा हो रहा है। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज में जरूरत से ज्यादा पानी जमा होने से करीब दो लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने से दिल्ली पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में युद्ध स्तर पर बचाव के प्रयास किये जाने की जरूरत है। अभी भी रुक–रुक कर होने वाली बारिश को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हालात चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।निस्संदेह, आज पूरी दुनिया में मौसम के चरम से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मौसम की तल्खी को देखकर लगता है कि प्रकृति के खिलाफ मानव की क्रूरता का कुदरत बदला ले रही है। जलधाराओं के मार्ग में लगातार बढ़ते अतिक्रमण ने नदियों के प्रवाह को आक्रामक बना दिया है। पहाड़ हमारी जरूरत हैं, हमारी प्राणवायु के संरक्षक हैं लेकिन वे सिर्फ इंसानी विलासिता और सैर–सपाटे के स्थान नहीं हैं। वे बड़ी विकास परियोजना व बड़े बांधों का बोझ उठाने लायक भी नहीं हैं। कहा जाता है कि बड़े बांधों के इलाकों में बादल फटने की घटनाएं बढ़ती हैं। इंसान ने विकास व पर्यटन तथा बस्तियों का जितना बोझ पहाड़ों पर लाद दिया है, वो इनकी क्षमता से अधिक है। पहाड़ों में विकास का आधार प्रकृति के साथ सामंजस्य होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर देश के महानगर व शहर अनियोजित विकास का त्रास झेल रहे हैं। थोड़ी सी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। बारिश के पानी के जो परंपरागत रास्ते थे, उन पर कब्जा करके हमने कंक्रीट के जंगल उगा दिये हैं। दूसरी ओर इस तरह की अतिवृष्टि आधारभूत ढांचे की पोल भी खोलती है। बड़े शहरों में सड़कों में जलभराव, रेलवे लाइन का पानी में डूबना व अंडरपास का जलमग्न होना अनियोजित विकास का ही परिणाम है। बारिश में हमारे आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता सामने आ जाती है। जिसके चलते सड़कों के धंसने और ट्रैफिक जाम की घटनाएं बारिश में सामने आती हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस मानसून का हम पलक–पांवड़े बिछा कर स्वागत करते थे, जो बारिश कभी आनंद का प्रतीक होती थी, वह अब डराने क्यों लगी हैं। कहीं न कहीं हमारे नगर नियोजक, प्रशासक, इंजीनियर व नीति नियंता भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने में विफल रहे हैं। जाहिर बात है, यदि आधारभूत ढांचे का निर्माण पर्याप्त योजना व दूरदर्शी सोच के अभाव में किया जाएगा, तो अतिवृष्टि से लोगों का मुश्किलों में फंसना स्वाभाविक ही है।

लोकतंत्र की जगह शोकतंत्र

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में जानलेवा हिंसा की खबरें बेहद चिंताजनक है। लोकतंत्र में मतों की गिनती होनी चाहिए, लेकिन ये चुनाव शोकतंत्र में तब्दील हो गए हैं, जहां मतों की जगह शवों की गिनती हो रही है। ये पहली बार नहीं है जब प.बंगाल में चुनावों के दौरान हिंसा हुई हो। इससे पहले 2013 के पंचायत चुनाव में 13 और फिर 2018 के पंचायत चुनावों में भी मतदान के दिन 14 लोगों की हिंसा की वजह से मौत हो गई थी। यही हालात लोकसभा और विधानसभा चुनावों में रहे। 2019 के लोकसभा चुनावों में 9 और 2021 के विधानसभा चुनावों में 16 मौतें प.बंगाल में हुई थीं। हिंसा के इस इतिहास को देखते हुए ये भी कहा जाने लगा कि प.बंगाल में चुनाव में हिंसा अब जानी–पहचानी बात है। ऐसी धारणा का बनना निश्चित ही लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। अगर किसी राज्य में चुनाव के दौरान हिंसा की आशंका हो, तो पहले से समूचे प्रशासनिक तंत्र और केंद्र व राज्य सरकार को मिलकर शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रतिबद्ध होकर उस आशंका को गलत साबित करने में जुट जाना चाहिए। लोकतंत्र किसी एक के भरोसे नहीं चल सकता। इसमें वाकई सबका साथ चाहिए। प.बंगाल में इस साथ की बहुत कमी दिखाई दी। 8 जून को पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से माहौल बिगड़ता दिख रहा था। मतदान के दिन ही 18 लोगों

की मौत हो गई और जून से लेकर अब तक कुल 37 लोग मारे जा चुके हैं। हिंसा की आशंका देखते हुए ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने छह जुलाई को कहा था कि 11 जुलाई को मतदान का नतीजा घोषित होने के बाद भी दस दिनों तक केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान राज्य में तैनात रहेंगे। लेकिन उच्च अदालत के निर्देश के बावजूद सुरक्षा इंतजामों में कहीं कोई बड़ी चूक हुई है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दुख इस बात का है कि हालात का तार्किक विश्लेषण करने की जगह एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप का खेल शुरु हो चुका है। लाशों पर राजनैतिक रोटी सेंकना किसे कहते हैं, प.बंगाल के हालात इस वक्त इसका जीता–जागता नमूना दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठे तो राज्य के चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने जवाब दिया कि कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, आयोग का काम पूरी व्यवस्था को संभालना है। उनका यह भी कहना है कि केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान अगर कुछ पहले राज्य में पहुंच गए होते तो हिंसा पर अंकुश लगाया जा सकता था। शनिवार दोपहर तक केंद्रीय बलों की 660 कंपनियां ही राज्य में पहुंची। जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 822 कंपनियों की मांग की थी।

वैसे इससे पहले चुनाव आयोग ने केवल 22 कंपनियां ही मांगी थी। फिर यह खींचतान राज्य में चली कि चुनाव केंद्रीय बलों की निगरानी में होने चाहिए या नहीं। हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

जहां उनकी अपील को खारिज करते हुए सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट के निर्देश को बरकरार रखते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा था कि श्चुनाव कराना हिंसा के लिए लाइसेंस नहीं हो सकता और हाईकोर्ट ने पहले हुईं हिंसा की घटनाओं को देखा है... चुनाव के साथ हिंसा नहीं हो सकती। अगर लोग अपने नामांकन ही नहीं दाखिल कर पा रहे हैं और उन्हें नामांकन करने जाते समय मार दिया जा रहा है तो मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कहां रह गए?च इसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से और आठ सौ कंपनियां भेजने का अनुरोध किया। लेकिन उसमें से आखिर तक 660 कंपनियां ही यहां पहुंचीं। इस समूचे घटनाक्रम को देखते हुए लगता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसका अनुमान होते हुए भी महज राजनैतिक वर्चस्व दिखाने के लिए लोगों की सुरक्षा से समझौता किया गया। अब जबकि 30 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, तमाम राजनैतिक दल एक–दूसरे पर उंगली उठाने लगे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिख कर राज्य में लोकतंत्र की बहाली के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। भाजपा की राज्य ईकाई ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग तक कर दी है। जिसे देखकर लगता है कि भाजपा मौके पर चौका लगाने की फिराक में ही बैठी है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में तो दो महीने से अधिक समय से हिंसा चल रही है, वहां न शांति बहाली की कोशिश भाजपा की ओर से हो रही है, न राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी कोई मांग हुई, क्योंकि राज्य में भाजपा की ही सरकार है। मगर प.बंगाल में सत्तारुढ़ टीएमसी के हाथों से शक्ति छीनने का यह माकूल अवसर भाजपा को दिख रहा है। इस ार ममता बनर्जी भी इसके लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं।

उनका तर्क है कि मृतकों में सबसे अधिक टीएमसी के लोग हैं। अनुभवी राजनेता ममता बनर्जी को यह तो पता होगा ही कि जो सत्ता में रहता है, पहली जिम्मेदारी उसकी बनती है। दूसरी बात यह कि आग जब फैलती है तो अपने–पराए का भेद किए बिना सबको खाक करती जाती है।

चुनाव के दौरान हुई हिंसा में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत को ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प.बंगाल में जब वामपंथी सरकार रही, तब भी चुनाव में हिंसा होती थी और अब तृणमूल कांग्रेस के लंबे शासन में भी हालात नहीं बदले हैं, तो इसका सीधा अर्थ यही है कि राज्य में राजनैतिक विभाजन इतना गहरा है कि जनता के साथ–साथ लोकतंत्र को चलाने वाली संस्थाएं भी इसमें बंट चुकी हैं। इसका एक ही तरीका है कि इसे एक या दूसरे की समस्या न मानकर समूचे लोकतंत्र की समस्या समझा जाए और उसी समग्रता के साथ उसका समाधान तलाशा जाए।

राज्यपाल की भूमिका पर विवाद

राज्यपालों की भूमिका के बारे में विवाद खड़े होना भारत में कोई नई बात नहीं है लेकिन अब जो नई बात हो रही है वह यह है कि कुछ राज्यपाल अब चुनी हुई सरकारों के उन प्रशासनिक कार्यों में भी दखल देने के प्रयास करने लगे हैं जिनकी जिम्मेदारी संविधानतः पूरी तरह किसी भी राज्य के मुख्यमन्त्री या उसके मन्त्रिमंडल की होती है। पहले विपक्षी दलों को यह आम शिकायत राज्यपालों से हुआ करती थी कि वे केन्द्र की विशेष राजनैतिक दल की सरकार के कहने पर संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं। केन्द्र व राज्यों के सम्बन्धों के बारे में सरकारिया आयोग की सिफारिशों से लेकर समय–समय पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों से भी निदेशक तालिका बनी। परन्तु राज्यपालों की नियुक्ति विशुद्ध राजनैतिक होती है अतः इसका आंशिक हल वाजपेयी सरकार के तत्कालीन गृहमन्त्री श्री लालकृष्ण अडवानी ने यह निकाला कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के बाद उस फैसले की तसदीक संसद के दोनों सदनों द्वारा भी करानी पड़ेगी जिसके न होने पर राष्ट्रपति शासन निरस्त हो जायेगा।

भारत के लोकतन्त्र के हित में यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। मगर इससे पहले 80 व 90 के दशकों में भारत में यह बहस भी चली थी कि किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले केन्द्र वहां के मुख्यमन्त्री से भी सलाह–मशविरा करके उसे विश्वास में ले। इस मुद्दे पर केवल बहस होकर ही रह गई मगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और बात आयी–गई हो गई। संवैधानिक रूप से राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति महोदय का है मगर भारत की संसदीय प्रणाली में इसे व्यवहारिक रूप में लागू करने के नियम भी जानते हैं। राज्यपालों का चुनाव केन्द्र सरकर द्वारा ही करके उन्हें नियुक्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है। बेशक राज्यपाल केवल राष्ट्रपति की प्रसन्नता के रहने तक ही अपने पद पर बना रह सकता है मगर वह भारत के संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और किसी भी राज्य में संविधान का पालन होते देखना उसका दायित्व होता है। मगर उस स्थिति में क्या किया जा सकता है जब स्वयं राज्यपाल ही संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम करने लगे और चुनी हुई सरकार के कार्यों में इस प्रकार अड़ंगा लगाने लगे कि उस जनता के वोट के अधिकार के कोई मायने ही न रहें जिसके बूते पर सरकार चुन कर आयी है। यहां सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राज्यपाल विधानसभा का अंग नहीं होता जबकि राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। अतः यह राज्यपाल के लिए जरूरी हो जाता है कि वह संविधान का शासन देखने की गरज से विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल तक अपने विचाराधीन न रखे। मगर तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि तो 2021 में इस राज्य के राज्यपाल निवास में जाने के बाद खुद को 'राजाधिराज' समझ रहे हैं और इस राज्य में अपनी समनान्तर सत्ता राजशाही की तरह ही चलाना चाहते हैं। हुजूर ने एक बार तो तमिलनाडु का नाम तक बदल दिया था। मगर विगत 8 जुलाई को इस राज्य की द्रमुक पार्टी के मुख्यमन्त्री श्री एम.के. स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीधे पत्र लिख कर जो रवि की शिकायत की है वह स्वतन्त्र भारत के लोकतान्त्रिक इतिहास की अनोखी घटना है।

उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा है कि आर.एन. रवि राज्य की शान्ति के लिए एक खतरा बन चुके हैं। किसी संवैधानिक मुखिया के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए यदि किसी राज्य की जनता द्वारा चुना हुआ मुख्यमन्त्री इस प्रकार के उदगार व्यक्त करता है तो यह संविधान की नजर से ही यह बहुत बड़ा प्रश्न है। स्टालिन ने आर.एन. रवि द्वारा किये गये कार्यों की शिकायत की पूरी फेहरिस्त राष्ट्रपति के पास भेजी है और कहा है कि वह राज्य में साम्प्रदायिकता भड़काने का काम कर रहे हैं। पाठकों को याद होगा कि श्री रवि ने पिछले दिनों किस तरह आधी रात को स्टालिन सरकार के एक मन्त्री को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिये थे जबकि मुख्यमन्त्री स्टालिन ने इस बाबत उनसे कोई सिफारिश नहीं की थी हालांकि उस मन्त्री पर भ्रष्टाचार के आरोप केन्द्रीय जांच एजेंसियों ने लगाये गये थे और उसे गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने पेश भी कर दिया था।

यह सीधे मुख्यमन्त्री के कार्य क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश था जिसकी वजह से राज्यपाल महोदय को एक घंटे बाद ही अपना आदेश निलम्बित करना पड़ा था। राज्यपाल के औहदे पर बैठे व्यक्ति की 'नीयत' का बहुत महत्व होता है। इसी राज्य में दस वर्षों तक पंजाब के मुख्यमन्त्री रहे अकाली दल के श्री सुरजीत सिंह बरनाला भी राज्यपाल रहे और केन्द्र में अलग–अलग राजनैतिक दलों की सरकारें भी रहीं मगर चेन्नई में कभी पत्ते तक के खड़कने की आवाज नहीं सुनी गई। मगर जब से श्री रवि सिंहासन पर बैठे हैं हर महीने कोई न कोई नया विवाद चेन्नई से लेकर दिल्ली तक को खड़कता रहता है। राज्यपाल को विशेष अधिकार तभी संविधान देता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान की शर्तों के दायरे में काम न कर रही हो अथवा वह बहुमत खो चुकी हो या उस राज्य में पूर्ण बहुमत की स्थायी सरकार बनना असंभव हो गया हो। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि किस राजनैतिक दल की बहुमत की सरकार है क्योंकि राज्यपाल का पद पूर्ण रुपेण 'अराजनैतिक' होता है।

इसी वजह से किसी भी राज्यपाल की कोई नीति तो होती ही नहीं है (क्योंकि नीति तो केवल चुनी हुई सरकार की ही होती है) बल्कि केवल 'नीयत' होती है। और यह नीयत हर परिस्थिति में संविधान के दायरे में रहते हुए ही होनी चाहिए। श्री रवि को संविधान सभा में राज्यपाल के पद के सृजन के बारे में चली लम्बी बहस को एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए और राज्य में संविधान के संरक्षक के प्रतिनिधि के गौरव को कायम रखना चाहिए।

वर्ल्ड कप पाकिस्तान की नौटंकी

आदित्य नारायण

पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की मेजबानी में होने वाले विश्वकप क्रिकेट के बायकाट की धमकी दी है। पाकिस्तान के खेल मंत्री अहसान मजारी ने कहा है कि भारत एशिया कप मैच न्यूट्रल वैल्यू पर खेलने की मांग को छोड़े वरना पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। हालांकि तथ्य यह है कि पाकिस्तान को वनडे वर्ल्ड कप का बायकाट करना संभव नहीं होगा अन्यथा उसे बहुत नुक्सान झेलना पड़ेगा। बायकाट करने की स्थिति में पाकिस्तान क्रिकेट जगत से पूरी तरह से अलग–थलग हो जाएगा। पाकिस्तान वैसे भी इन दिनों अलग–थलग ही पड़ा हुआ है। वर्ल्ड कप नहीं खेलने की स्थिति में इंटरनैशनल क्रिकेट काउंसिल उस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है और पाकिस्तान में 2025 में होने वाली चौम्पियंस ट्राफी भी खटाई में पड़ सकती है। यह सर्वविदित है कि भारत के बिना किसी भी आईसीसी का कोई भी सफल आयोजन संभव नहीं है क्योंकि ऐसे आयोजनों में 80 फीसदी कमाई भारतीय दर्शकों से ही होती है। भारत–आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को छोड़कर अन्य देशों के क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से मिलने वाले फंड पर ही निर्भर हैं। यह फंड आईसीसी सभी बोर्ड को बांटती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसी फंड पर जिंदा है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप को लेकर नौटंकी क्यों कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की घरेलू राजनीति का ही परिणाम है। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार भारत का विरोध करके अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। पाकिस्तान की सरकार कम से कम ऐसा दिखाना चाह रही है कि वह भारत से बदला लेना चाहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई वर्षों से संबंध काफी कड़वे चल रहे हैं। द्विपक्षीय तनाव, लगातार युद्ध विराम उल्लंघन की घटनाएं और कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद के कारण संबंधों में जहर घुलता गया। दोनों देशों के बीच क्रिकेट कूटनीति 1980 के दर्शक की है। दोनों देशों के संबंधों को मधुर बनाने के लिए क्रिकेट को एक उपकरण के रूप में उपयोग के लिए अधिकतर भारतीय नेताओं ने कई प्रयास किए लेकिन आतंकवादी घटनाओं ने सब कुछ विफल कर दिया।

भारत सरकार का स्पष्ट स्टैंड है कि आतंकवाद और वार्ता साथ–साथ नहीं चल सकते। यह भी सत्य है कि भारत–पाकिस्तान क्रिकेट कूटनीति के चलते पूर्व में संबंधों की बर्फ भी कई बार घपिघली है लेकिन पाकिस्तान ने हमें लगातार जख्म दिये हैं जिससे भारत सरकार को कड़ा स्टैंड लेना पड़ा है। 2012 के बाद से दोनों देशों के बीच एक भी द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेली गई है। हालांकि दोनों देशों के बीच आईसीसी के बड़े टूर्नामेंटों में मुकाबले देखने को मिल जाते हैं। दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध पाकिस्तान की सियासत के चलते खराब हुए। दोनों देशों की आवाम क्रिकेट की दीवानी है। जब भी भारत और पाकिस्तान क्रिकेट में आमने–सामने होते हैं तो उसका एक अलग ही रोमांच होता है। भारत–पाक क्रिकेट मैच को एक खेल की तरह नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी देखा जाता है। दोनों देशों की प्रतिद्वद्विता क्रिकेट के मैदान से बाहर भी नजर आती है। पाकिस्तान के तानाशाह हुक्मरान जिया उल हक (जिया जालंधरी) से लेकर परवेज मुशर्रफ तक क्रिकेट कूटनीति के चश्मदीद रहे हैं। क्रिकेट विशेषज्ञ बताते हैं कि 1999 में भारत और पाघकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध चल रहा था उन दिनों इंग्लैंड में विश्वकप क्रिकेट भी चल रहा था। तब माना जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान का मैच रद्द करना पड़ेगा क्योंकि दोनों देशों की जंग के बीच खेलना आसान नहीं था। इसके बावजूद भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट मैच हुआ और भारत और पाकिस्तान प्रेघमियों ने स्टेडियम में दोनों टीमों का जोरदार स्वागत किया। भारत–पाकिस्तान मैचों को देखने के लिए पाकिस्तान के लोग भारत आते रहे हैं और भारतीय पाकिस्तान जाते रहे हैं। यह बात जगजाहिर है कि भारत और पाकिस्तान की आवाम के बीच संबंध बने हुए हैं लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान ने हर वक्त आवाम में दूरियां पैदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने हमें बहुत से जख्त दिए। मुम्बई के बम धमाके, 26ध्11 का मुम्बई हमला। लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर भारत की संसद पर हमला। उड़ी में भारतीय जवानों पर हमला और यहां तक कि जम्मू के रघुनाथ मंदिर से लेकर गुजरात के अक्षरधाम मंदिर तक निर्देषों का खून बहाया गया। अंततः भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की वार्ता करने से इंकार घ्कर दिया। भारत सरकार ने महसूस किया कि ऐसी मुलाकातों का क्या फायदा। सुबह भी आते रहिए, शाम भी आते रहिए। दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। भारत और पाकिस्तान का आवाम और क्रिकेटर दोनों देशों के संबंधों में मधुरता चाहते हैं। ऐसे में क्रिकेट संबंधों से दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल सकती है। भारत तो बस यही चाहता है कि पाकिस्तान सरहद पार से मौत के सौदागर न भेजे और बंदूकों के बल मौसम बदलने का ख्वाब न देखे। क्रिकेट कूटनीति का साधन हो सकता है विकल्प नहीं।

नए भारत को चाहिए नया प्रशासनिक ढांचा

ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर का भग्नावशेष बना भारत का प्रशासनिक ढांचा देश की तेजी से बढ़ती आबादी और विविधतापूर्ण एवं समयानुकूल आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम नहीं दिख रहा। कालातीत हो चुका यह ढांचा देश की प्रगति को अवरुद्ध कर सक्षम एवं प्रभावी जन सेवाएं प्रदान करने में नाकाम हो रहा है। इसलिए देश के बेहतर भविष्य के लिए प्रशासनिक सुधार कोई विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्य हो गए हैं। कई विद्वान एवं विश्लेषक समय–समय पर इनकी आवश्यकता बताते रहे हैं। जैसे कि औपनिवेशिक प्रशासनिक अमले की विरासत से उपजी चुनौतियों को लेकर प्रतिष्ठित राजनीति विज्ञानी एवं संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल आस्टिन ने दर्शाया था कि इस प्रणाली में लचीलेपन का अभाव है और यह नागरिकों के अनुसार स्वयं को ढालने और आकार ले रहे सामाजिक परिवर्तनों से ताल मिलाने में अक्षम है। संविधान शिल्पी और सामाजिक न्याय के प्रवर्तक डा. बीआर आंबेडकर ने भी समतामूलक समाज के निर्माण में प्रशासनिक सुधारों की महत्ता को रेखांकित किया था। उनका कहना था कि औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों वाला प्रशासनिक ढांचा देश के समक्ष विद्यमान सामाजिक–आर्थिक विषमताओं के समाधान में प्रभावी रूप से उपयोगी नहीं हो सकता। अब सक्षमता, पारदर्शिता, जवाबदेही और तत्परता जैसे पहलुओं के आधार पर प्रशासनिक ढांचे को नए सिरे से खड़ा करने के लिए सुधारों की मांग जोर पकड़ रही है। इसका उद्देश्य ऐसी नौकरशाही का निर्माण करना है जो लोगों की सेवा करे, विकास को गति दे और सभी नागरिकों तक समान अवसर सुनिश्चित कर सके। इसमें भ्रष्टाचार पर प्रहार, अक्षमताओं से मुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और तकनीकी का लाभ उठाने पर जोर है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में नागरिकों की आकांक्षा पूर्ति की दिशा में ऐसे सुधारों के लिए ढांचागत बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में, प्रशासनिक ढांचे पर चढ़ी औपनिवेशिक खुमारी उतारकर एक ऐसे प्रशासनिक तंत्र की राह प्रशस्त करना आवश्यक हो चला है जो विशुद्ध भारतीय चरित्र एवं मूल्यों से ओतप्रोत हो। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में प्रशासनिक सुधार महज आवश्यकता न होकर राष्ट्र की प्रगति, विस्तार एवं संसाधनों की उचित साझेदारी के लिए एक पूर्वनिर्धारित शर्त बन गई है। अक्षमता और भ्रष्टाचार प्रभावी लोक सेवाओं की राह में बड़े अवरोधक हैं। भ्रष्टाचार लोक सेवाओं की गुणवत्ता घटाने के साथ ही शासन में जनता के भरोसे को भी घटाता है। इसलिए सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में भ्रष्टाचार से निपटना बड़ी चुनौती है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने लाभार्थियों के खाते में सीधे रकम पहुंचाकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ी पहल की है। इससे सरकारी संसाधनों का रिसाव रुका है। हालांकि, राष्ट्रजीवन के कुछ अन्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का दंश अभी भी लोगों को चुभ रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस का मामला ही ले लीजिए। इसमें कई बार अपात्र लोगों को भी लाइसेंस मिल जाता है। ऐसे लोग गाड़ी चलाते हुए न केवल खुद के लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी जोखिम बन जाते हैं। वहीं, पात्र लोगों को भी जेब ढीली करनी पड़ जाती है। दोनों स्थितियों के लिए भ्रष्टाचार जिम्मेदार है, जिस पर लगाम लगानी होगी और यह सुधारों के बिना संभव नहीं होगा। प्रशासनिक सुधारों के पीछे मंशा केवल एक ढांचे का कायाकल्प करना ही नहीं, बल्कि लोक सेवाओं को और बेहतर बनाने के साथ ही नागरिकों की बदलती आवश्यकताओं की कसौटी पर खरा उतरने की भी है। इस दिशा में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस बल, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में सुधार भी करने होंगे। इसमें पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी अहम पहलू हैं, क्योंकि किसी समाज के जागरूक एवं सक्रिय बनते जाने पर इन्हें लेकर मांग और मुखर होती जाती है। जनस्तर पर आकार ले रहा परिवर्तन भी प्रशासनिक सुधारों की मांग को गति दे रहा है। ऐसे सुधारों में तकनीक को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं आधुनिक एवं सुसंगत बनेंगी। भारतीय प्रशासनिक ढांचे में जिला स्तरीय इकाई बहुत महत्व रखती है, पर कई कारणों से वे खासी अक्षम बनी हुई हैं। इसमें शक्ति का अति–केंद्रीकरण प्रमुख है, जिसमें ताकत राज्य स्तर पर केंद्रित रहती है।

आज का राशिफल

मेष :– व्यापार में विकास के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। धन के लेनदेन में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर में सुख–शांति का वातावरण बना रहेगा।

वृषभ :– मन को स्थिर रखने की सलाह गणेशजी देते हैं, क्योंकि अर्निणय की मनोदशा से अवसर गवां सकते हैं। प्रवास का आयोजन टाल दें। नए कार्य प्रारंभ न करें।

मिथुन :– लक्ष्मीजी की कृपा से दिन लाभदायी होगा। उत्तम भोजन, सुंदर वस्त्र व अपनों के साथ से दिन आनंददायी होगा।

कर्क :– कोई भी महत्त्वपूर्ण निर्णय न लें। संबंधियों से मनमुटाव हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानहानि एवं धनहानि से बचें।

सिंह :– आज का दिन लाभदायी है। मित्रों से लाभ और पर्यटन की संभावना है। हाथ आया अवसर जा सकता है, इसलिए निर्णय टाल दें। व्यापार एवं आर्थिक लाभ के योग हैं।

कन्या :– आज दिन शुभ है। नए कार्य संपन्न होंगे। व्यापारी व नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। व्यापार में लाभ व नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। पिता से लाभ होगा।

तुला :– व्यावसाय में लाभ की संभावना है ऐसा गणेशजी कहते हैं। नौकरी व व्यापार में सहकर्मियों से सहयोग नहीं मिलेगा। लंबी यात्रा का आयोजन हो सकता है। अस्वस्थ रहेंगे।

वृश्चिक :– आज शांति व सावधानीपूर्वक रूप से रहने की गणेशजी की सलाह है। नए कार्यों में असफलता के योग हैं। क्रोध पर संयम रखें। सरकार विरोधी प्रवृत्तियों से दूर रहें।

धनु :– आज का दिन आनंदपूर्वक बीतेगा। सहवास का आनंद मिलेगा। प्रवास, पर्यटन होगा। लेखनकार्य के दिन अनुकूल है। साझेदारी से लाभ होगा।

मकर :–आज का दिन शुभ और फलदायी होगा। महत्त्वपूर्ण निर्णय न लेने की सलाह है। यात्रा के योग हैं। लेखनकार्य के लिए अच्छा दिन है। महिला के साथ विवाद में न उतरें।

कुंभ :– आप की वाणी व विचारों में शीघ्र परिवर्तन होगा। बौद्धिक चर्चा में शामिल होंगे। आकस्मिक खर्च की आशंका है। पाचन न होने जैसी बीमारियों से परेशान होंगे।

मीन :– गणेशजी कहते हैं कि आप में उत्साह व स्फूर्ति की कमी होगी। परिजनों के साथ विवाद न करें। अस्वस्थ महसूस करेंगे।

युवक का शव रेलवे लाइन पर मिलने से मचा हड़कंप

पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी

जौनपुर। खेतासराय थान अंतर्गत अयोध्या जौनपुर रेल प्रखंड के खेतासराय रेल लाइन पर बुधवार की भोर में 21 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के शरीर में चोट के निशान थे।युवक की पहचान थाना क्षेत्र के अहिरों परशुरामपुर निवासी विशाल राजभर के रूप में हुई है। उधर से गुजर रही ट्रेन के चालक ने जीआरपी शाहगंज को सूचना दी।

इसके बाद जीआरपी शाहगंज, खेतासराय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

मृतक के गांव के लोगों ने हत्या के पीछे आशनाई की आशंका जाहिर किया है। युवक के कुछ दोस्त की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।

जो उसे भोर में मोबाइल फोन करके घर से बुलाए थे।

खेतासराय थाना क्षेत्र के अहीरों परशुरामपुर निवासी प्रदीप राजभर चंडीगढ़ शहर में रहकर बेकरी में

काम करते हैं। उनके परिवार में दो बेटे हैं। बड़ा बेटा विशाल राजभर जौनपुर के एक कालेज से स्नातक का छात्र है। छोटा बेटा गांव में ही पढ़ाई करता है। पत्नी घर पर रहकर खेती बारी का काम देखती है। बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रदीप राजभर का बड़ा बेटा 21 वर्षीय विशाल राजभर रोज की तरह घर में खाना खाकर सोया हुआ था।तीन बजे भोर में उसके मोबाइल पर किसी दोस्त का फोन आया। इस दौरान हुई बातचीत के बाद वह घर से परिवार वालों को बिना बताए पैदल निकल लिया। उधर परिवार वाले युवक को घर में नहीं देख परेशान हो गए ।पहले उन्होंने आसपास खोजा फिर उसके मोबाइल पर फोन करके काफी खोजबीन में जुट गए।

जौनपुर शाहगंज रेल प्रखंड पर खेतासराय थाना अंतर्गत तारगहना गांव जाने वाले मोड़ पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया।

ग्रामीणों के अनुसार तीन बजे भोर में उधर से गुजर रही एक ट्रेन के चालक ने रेलवे लाइन पर युवक का शव देखते ही ट्रेन रोककर शाहगंज जीआरपी को सूचना दिया। इसके तत्काल बाद राजकीय रेलवे पुलिस शाहगंज और खेतासराय थाने के इंस्पेक्टर राजेश यादव, उपनिरीक्षक महंगू यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को रेलवे लाइन से उठाकर किनारे रखकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। मृतक युवक की जेब में एक मोबाइल पर लगातार घंटी बज रही थी। जिसे परिजन फोन कर रहे थे। एक राहगीर ने फोन को निकाल कर कॉल रिसीव किया और उनके परिजनों को सूचना दिया।

प्रत्यक्ष तौर पर घटना को देखने से लगता है युवक की हत्या करके उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए रेलवे लाइन पर लिटा दिया गया था।पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है।

योगी कैबिनेट में 17 प्रस्ताव पास

यूपी के पहले सुपर अल्ट्रा प्लांट को मिली मंजूरी, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर की रोड होगी चौड़ी

संवाददाता

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में हुई। इसमें 17 प्रस्ताव पर सहमति बनी। कैबिनेट से बिजली की किल्लत दूर करने वाला प्रस्ताव भी पास हुआ। एनटीपीसी को ओबरा में 800 मेगा वॉट के दो प्लांट लगाने की मंजूरी मिली है। जिसका नाम ओबरा डी होगा। जो कि 500 एकड़ में बनेगा। यूपी सरकार और एनटीपीसी का 50–50: होगा। 30: राज्य सरकार देगी। 70: बैंक से लोन लेकर तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला सुपर अल्ट्रा प्लांट होगा। इसका बजट 17985 करोड़ होगा। पहली यूनिट 5 महीने में और दूसरी यूनिट उसके 6 माह में बन जाएगी।रामपुर जिले में रामपुर, शाहबाद, बाजपुर मार्ग पर सड़कों की लम्बाई और चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। साथ ही, सुंदरीकरण के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। ये रामपुर शाहबाद स्वार से होते हुए उत्तराखंड के जिम कार्बेट तक जानी है।मां विंध्यवासिनी जी के कॉरिडोर के रास्ते का चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जनपद चित्रकूट में

तहसील मानिकपुर में बनने का प्रस्ताव पास हुआ है। मिशन वात्सल्य योजना को मंजूरी दी गई है। बाल संरक्षण योजना का नाम परिवर्तित करके वात्सल्य योजना किया गया है। कुशीनगर में नई जेल के निर्माण के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। 1 हजार से अधिक बंदियों की क्षमता वाली नई जेल होगी। हाथरस में भी 1 हजार से अधिक बंदियों की क्षमता वाली नई जेल के लिए 184 करोड़ रुपए की कैबिनेट में स्वीकृति मिली है। केंद्र सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेज योजना के संबंध में प्रतापगढ़ स्वशासी मेडिकल कॉलेज के जीर्ण–शीर्ण भवन के ध्वस्तीकरण के संबंध मे प्रस्ताव पास किया गया है। उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र के टी.एस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ के स्थापना के संबंध मे प्रस्ताव पास किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को कालिदास मार्ग में उनके आवास पर हुई। इसमें 14 बड़े प्रस्तावों पर सहमति बन गई। यूपी में 15950 करोड़ से 4 डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। इससे 4 हजार लोगों को नौकरियां मिल सकेंगी। इसमें एक पार्क ग्रेटर नोएडा में तैयार किया जा रहा है। इसको बनाने का ठेका मुंबई के हीरानंदानी समूह को मिला है।

अपराध शाखा लखनऊ, क्राइम टीम (डीसीपी उत्तरी) व थाना गाजीपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गाजीपुर थाना क्षेत्रान्तर्गत व उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में लूट की घटना कारित करने वाले अन्तर्जनपदीय दो शातिर लूटरों को किया गया गिरफ्तार

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। पुलिस आयुक्त एस0बी0 शिरडकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय आकाश कुलहरि के निर्देशन में, पुलिस उपायुक्त उत्तरी एस०एम०कासिम आब्दी, अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी अभिजित आरशंकर के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर दिलीप कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गाजीपुर सुनील कुमार सिंह, क्राइम ब्रांच के निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्रा व क्राइम टीम प्रभारी (उत्तरी) विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में मय पुलिस फोर्स द्वारा 12.07.2023 समय 07रू20 बजे थाना गाजीपुर लखनऊ क्षेत्र में स्थित शेरवुड एकेडमी से आगे आयुर्वेद संस्थान के पास से 02 नफर अभियुक्तगण क्रमश 1–मो0 आसिफ खान उर्फ आर्यन उर्फ चाइना पुत्र तनवीरुल हसन निवासी जरवा रोड तुलसीपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर हाल पता– फ्लैट नं0– 205 तैयबा अपार्टमेन्ट पन्तनगर थाना इन्दिरानगर जनपद लखनऊ उम्र– 29 वर्ष व 2– इन्द्रजीत ओझा उर्फ छोटू उर्फ बाबू पुत्र शिवदेव ओझा निवासी 16ध्21 कन्हईपुर निकट पावर हाउस थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज मूल पता– ग्राम परसया थाना हल्दी जनपद बलिया वर्तमान पता– फ्लैट नं0– 205 तैयबा अपार्टमेन्ट पन्तनगर थाना इन्दिरानगर जनपद लखनऊ उम्र– 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से घटना में लूटे गये नगदी बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः–

दिनांक 12.07.2023 को निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार राम मय हमराह फोर्स के थाना गाजीपुर लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 286ध्2023 धारा 392 भादवि के अभियुक्तगण की तलाश व सुरागरसी पतारसी तथा बाउम्मीद गिरफ्तारी कल्याण अपार्टमेन्ट के पास मौजूद थे कि मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि सेक्टर 25 के पास स्थित पावर हाउस जन सेवा केन्द्र से दिनाँक 08ध्07ध्2023 को लूट की घटना कारित करने वाले जंगल वाली रोड के किनारे से शेरवुड एकेडमी से आगे आयुर्वेद संस्थान की तरफ आ रहे हैं तभी जंगल रोड किनारे से होकर एक स्कूटी आती हुई दिखाई दी, जिसके चलाने वाला व्यक्ति हेलमेट लगाये था तथा दोनो काले रंग की शर्ट पहने हुए रोड लाइट की रोशनी में दिखाई दिये, जिनकी ओर इशारा करके मुखबिर ने बताया कि वहीं दोनो व्यक्ति है जिन्होंने पावर हाउस जन सेवा केन्द्र से रुपयो की लूट की घटना की है इसके उपरान्त मुखबिर चला गया। स्कूटी सवार दोनो व्यक्ति जब पुलिस बल की जद में आ गये तो निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार के इशारा करने पर समस्त पुलिस बल आड़ से निकल कर स्कूटी सवार व्यक्तियों को रोका गया जो एकाएक पुलिस बल को देखकर मुड़कर भागने का प्रयास करने लगे जिन्हे दौडाकर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए आयुर्वेद संस्थान से करीब 20 मीटर दूर सड़क पर ही पकड़ लिया गया। भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि हम दोनो ने सेक्टर 25 चौराहा पावर हाउस से जहाँ बिल जमा होता है वहाँ से रुपये लूट कर भाग गये थे। गाडी चला रहे व्यक्ति से हेलमेट उतरवाकर नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मो0 आसिफ खान उर्फ आर्यन उर्फ चाइना पुत्र तनबीरुल हसन निवासी जरवा रोड तुलसीपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर हाल पता– फ्लैट नं0– 205 तैयबा अपार्टमेन्ट पन्तनगर थाना इन्दिरानगर जनपद लखनऊ उम्र– 29 वर्ष तथा दसरे ने अपना नाम इन्द्रजीत ओझा उर्फ छोट उर्फ बाब पत्र शिवदेव ओझा निवासी 16ध्21कन्हईपुर निकट पावर हाउस थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज मूल पता– ग्राम परसया थाना हल्दी जनपद बलिया वर्तमान पता– फ्लैट नं0–205 तैयबा अपार्टमेन्ट पन्तनगर थाना इन्दिरानगर जनपद लखनऊ उम्र– 33 वर्ष बताया। मो0 आसिफ खान उर्फ आर्यन उर्फ चाइना उपरोक्त की जामातलाशी से उसके कब्जे से एक अदद रिवाल्वर 32 बोर देशी व 04 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर व एक अदद मोबाइल वन प्लस कम्पनी आसमानी रंग बरामद हुआ तथा 105600ध्– रूपया नगद बरामद हुआ दूसरे इन्द्रजीत ओझा उर्फ छोटू उर्फ बाबू उपरोक्त के पास से कुल 112300ध्– रूपया बरामद हुआ। भागने का कारण पूछने पर दोनो ने एक स्वर में बताया कि इसी रिवाल्वर को दिखाकर हम लोगो ने सेक्टर 25 चौराहा पावर हाउस के अन्दर जहाँ बिल जमा होता है वहाँ से 3,50,000ध्– रुपये लूटे थे। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध विभिन्न जनपद में अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका।–

अभियुक्तगण लखनऊ मे घूमकर जगहों की रेकी करते हैं उसके बाद असलहे की नोक पर लूट करके भाग जाते है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में

क्राइम ब्रांच लखनऊ

शिवानन्द मिश्र प्रभारी निरीक्षक थाना मड़ियाव व

क्राइम टीम पुलिस उपायुक्त उत्तरी, उप निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह,

प्रभारी निरीक्षक क्राइम ब्रांच

हेड कांस्टेबल अतुल पाण्डेय

उत्तरी क्राइम टीम प्रभारी लखनऊ

हेड कांस्टेबल नदीम, सरताज अहमद

इन्द्र प्रताप सिंह

अवधेश गिरी

आजम,जीत सिंह, विश्वजीत, वीर सिंह,कांस्टेबल सूरज सिंह

हेड कांस्टेबल मिथलेश गिरी, सन्तोष कुमार,कांस्टेबल विशेष दुहून,

मुकेश,अजीत सिंह,मधुमे, अतिरिक्त निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार राम,उप निरीक्षक भरत कुमार पाठक, उपनिरीक्षक अजीत कुमार, उपनिरीक्षक रामधीरज यादव उपनिरीक्षक नितिन कुमार, उपनिरीक्षक कुलदीप सिंह, उपनिरीक्षक अक्षय कुमार, हेड कांस्टेबल बालकुश यादव हेड कांस्टेबल सोमल पासवान, कांस्टेबल दलवीर सिंह, थाना गाजीपुर, लखनऊ शामिल रहे। उल्लेखनीय है कि डी. सी.पी. नार्थ द्वारा गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25000ध्– रू) के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सांस्कृतिक दल होंगे पुरस्कृत : जयवीर

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वादयंत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु तैयार की गई कार्ययोजना के तहत एक सेट वाद्ययंत्र के क्रय हेतु 30 हजार रूपये की धनराशि दी जायेगी। वाद्ययंत्रों का उपयोग प्रदेश के सांस्कृतिक उन्नयन, सांस्कृतिक विरासत का रक्षण, पर्यटन संवर्द्धन, स्वच्छ भारत मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तथा ग्रामीण संस्कृति को अच्छुण रखने एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु उपयोग किया जायेगा।

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्कृष्ट प्रस्तुतीकरण करने वाले दल को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान धारक को पुरस्कृत किया जायेगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दल को 51 हजार, द्वितीय को 21 हजार तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दल को 11 हजार रूपये की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी। इन टीमों के चयन हेतु एक प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी तथा पुरस्कारों के चयन हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा जो पुरस्कारों हेतु समस्त कार्यवाही पूर्ण करेगी। डीएम, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की संस्तुति पर सराहनीय प्रस्तुतीकरण देने वाले टीम को पुरस्कार दिया जायेगा।

पुरस्कार हेतु गठित समिति में निदेशक संस्कृति निदेशालय अध्यक्ष, वित्त नियंत्रक संस्कृति निदेशालय सदस्य, जिला सूचना अधिकारी लखनऊ सदस्य तथा निदेशक संस्कृति द्वारा नामित सहायक निदेशक संस्कृति सदस्य सचिव होंगे। उन्होंने बताया कि लोक कलाकारों को संस्कृति विभाग से जोड़ने से लोक कलाओं का संवर्द्धन एवं लोक विरासत का संरक्षण भी होगा और कलाकारो को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी प्राप्त होगा।

भाजपा 2024 में भी करेगी फतह : भूपेंद्र

संवाददाता

लखनऊ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा,जिस प्रकार 2014, 2017, 2019 व 2022 का चुनाव जीते थे। उसी तरह से 2024 का भी चुनाव बीजेपी जीतेगी। बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है और उसी के आधार पर वह आगे चल रही है। मंगलवार को काशी व गोरखपुर क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आजमगढ़ में मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार चार चुनाव हार चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 400 सीटें जीतने का दावा किया था।

आप की छात्र विंग के पन्द्रह जनपदों के जिलाध्यक्षों की सूची जारी

संवाददाता

लखनऊ। आम आदमी पार्टी ने संगठन विस्तार के क्रम में अपनी छात्र विंग, सीवाईएसएस यानि छात्र युवा संघर्ष समिति की पन्द्रह जनपदों के जिलाध्यक्षों की घोषणा करते हुए प्रथम सूची जारी कर दिया हैं।छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह की स्वीकृति के बाद पन्द्रह जनपदों की यह प्रथम सूची जारी की गई हैं, अभी आगे भी घोषणा होगी। प्रथम सूची में आशीष राठौर को जिलाध्यक्ष अलीगढ़ नियुक्त किया गया हैं, ऐसे ही अमन यादव को जिलाध्यक्ष कानपुर नगर नियुक्त किया गया हैं, इमरान को जिलाध्यक्ष मुरादाबाद नियुक्त किया गया हैं, विशाल शर्मा को जिलाध्यक्ष आगरा नियुक्त किया गया हैं, गगन खन्ना को जिलाध्यक्ष लखीमपुर नियुक्त किया गया हैं, रवि प्रकाश शर्मा को जिलाध्यक्ष कुशीनगर नियुक्त किया गया हैं, आकाश यादव को जिलाध्यक्ष बलरामपुर नियुक्त किया गया हैं, शोयब को जिलाध्यक्ष मेरठ नियुक्त किया गया हैं, दिव्यांशु द्विवेदी को जिलाध्यक्ष महोबा नियुक्त किया गया हैं, जुबिन चौधरी को जिलाध्यक्ष झाँसी नियुक्त किया गया हैं, अमरीश चौबे को जिलाध्यक्ष बलिया नियुक्त किया गया हैं, नवनीत सिंह को जिलाध्यक्ष हमीरपुर नियुक्त किया गया हैं, मोहम्मद जुबेर को जिला अध्यक्ष बरेली नियुक्त किया गया हैं, गौरव सिंह को जिलाध्यक्ष वारणसी नियुक्त किया गया हैं इमरान खान को जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद नियुक्त किया गया हैं।

विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव में दिया जा रहा पर्यावरण संरक्षण पर जोर

संवाददाता

लखनऊ। पर्यावरण एवं जल संरक्षण के संकल्प के साथ आयोजित किए जा रहे विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव कार्यक्रम की सराहना करते हुए पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ अरुण कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को पर्यावरण एवं जल संरक्षण के महत्व के बारे में ना केवल जानकारी प्राप्त होगी बल्कि वह इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने समाज और राष्ट्र के प्रति अहम भूमिका भी निभाएंगे। आज अपने आवास पर पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री ने चल रहे विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव कार्यक्रम को लेकर सामाजिक संस्था सोसायटी आफ करियर टेक्सोनोलॉजी (सोक्ट) के अध्यक्ष डॉ अगम दयाल एवं जनविकास महासभा के अध्यक्ष पंकज कुमार से मुलाकात के दौरान यह बातें कहीं। इस दौरान विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव के अन्तर्गत होने वाले कार्यक्रमों की पूरी जानकारी देते हुए डॉ. अगम दयाल ने बताया कि जनविकास महासभा एवं सामाजिक संस्था सोक्ट के माध्यम से विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव का प्रारंभ किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण एवं जल संरक्षण स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता नशा मुक्त समाज आत्मनिर्भर भारत के महत्व के प्रति जागरूक करने के साथ–साथ उनके अंदर छिपी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित भी करना है। इस अवसर पर जनविकास महासभा के अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि आज के विद्यार्थी कल के राष्ट्र निर्माता होंगे इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों में आज से ही पर्यावरण एवं जल संरक्षण स्वास्थ्य शिक्षा नशा मुक्त समाज आत्मनिर्भर भारत के महत्व इत्यादि के प्रति जागरूक किया जाए और इस समाज और राष्ट्र के लिए उनकी जिम्मेदारियों के प्रति उन्हें जागरूक किया जाए इसके लिए ही विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव की शुरुआत की गई है यह वर्ष भर छोटे–छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों विद्यार्थियों के मध्य जागरूकता का कार्य करेगा।

सितंबर में होगा मिसेज यूपी,यूपी के 7 शहरों में होगा ऑडिशन

संवाददाता

लखनऊ। विवाहित महिलाओं के लिए सितंबर में मिसेज उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। क्वीनीफाइड ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से होने वाली इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश की महिलाओं को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इसके लिए यूपी के 7 शहर लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ और बरेली में ऑडिशन लिया जाएगा। यहां से जिन महिलाओं का चुनाव होगा उनको लखनऊ में होने वाले फाइनल में मौका मिलेगा। अभी तक यूपी में इसके दो सेशन हो चुके हैं। यह तीसरा सत्र होने जा रहा है। मिसेज यूपी की आयोजन मंडल में शामिल प्रीति यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता से जिनका चुनाव होता है उनको कई बड़े प्लेटफॉर्म मिलते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल इस प्रतियोगिता को जीतने वाली महिला को फीलिपिंस में आयोजित मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिल रहा है। वह अक्टूबर महीने में वहां जा रही है। इससे पहले की प्रतियागिता में जीतने वाले महिलाओं को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सम्मानित किया था। यहां से जीती हुई प्रतियोगी को उप्र खादी बोर्ड ने अपना फेस बनाया था।

ऐसे में उनको एक बड़ा मंच भी मिलता है। बताया कि यहां से जीती हुई इशिका द्विवेदी और नीतिका राणा मिसेज इंडिया सीओ 2023 में हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं।

मायावती बोलीं, वर्षा प्रभावित पीड़ित परिवारों की मदद करें सरकारें

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से उपजे विकट हालात पर चिंता जताते हुए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने केन्द्र और प्रभावित राज्यों की सरकारों से बैठक और आकलन के बजाय पीड़ित परिवारों की आगे बढ़ कर मदद करने की मांग की है। मायावती ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि " यूपी सहित देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश व बाढ़ के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित है। काफी जान–माल व पशुधन की हानि हुई है। शहरों का बुरा हाल है, किन्तु ग्रामीण इलाकों में लोगों के मकान गिरने व फसल की व्यापक बर्बादी आदि के कारण हालात काफी गंभीर व चिन्ताजनक है।

प्रवर्तन जोन–7 में अवैध निर्माणों का अंबार

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण का जोन–7 जो पुराना शहर में आता है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है। यहां पर ऐतिहासिक महत्व की एवं तमाम धरोहरें मौजूद हैं। साथ ही यह क्षेत्र घनी आबादी के रूप में बसा हुआ है, यहां पर अब कोई भी जगह खाली नहीं है, इसलिए यहां पर जब भी कोई इमारत बनती है, तो पुरानी इमारत तोड़कर ही बनती है, जिसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने तमाम नियमवाली बना रखी है, ताकि ऐतिहासिक धरोहरों की यथा स्थिति बनी रहे, और कोई अतिक्रमण ना होने पाए, और पुराना शहर अपने इतिहासिक महत्व को बरकरार रखते हुए सुनियोजित ढंग से विकसित होता रहे। इस जोन में चौक, ठाकुरगंज, सहादतगंज, तालकटोरा बाजार खाला आंशिक काकोरी आदि क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में प्रवर्तन जोन–7 सहायक अभियंता उदयवीर सिंह के संरक्षण में सैकड़ों अवैध निर्माण चल रहे हैं। समय समय पर पत्रकारों द्वारा इन अवैध निर्माणों की खबर विभिन्न प्लेटफार्म पर चलाई जाती है। जिस पर सहायक अभियंता का कहना है, कि खबर चाहे जितनी चला ले मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरी पहुंच शासन तक है, और डिप्लोमा इंजीनियर्स संगठन में प्रदेश महासचिव ऐसे ही नही बना हूं। प्रवर्तन जोन–7 में अधिकारियों की संलिप्तता से चल रहे हैं, धुआंधार अवैध निर्माण, जनहित में जनता द्वारा कई बार अवैध निमाणो की शिकायत की गई। लेकिन अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही सहायक अभियंता पर? जिम्मेदार अधिकारी मौन है। जिस तरह का माहौल प्रवर्तन जोन–7 में बना हुआ है, यह विकास प्राधिकरण पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, यह प्राधिकरण है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्रवर्तन जोन–7 में हो रहे अवैध निर्माणों पर सहायक अभियंता बात करने से सीधे मना करते हैं, और अपने अधीनस्थ अवर अभियंताओं से भी बात नही करने देते, कहतें हैं प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने मना किया है, प्रवर्तन से सम्बन्धित से अवैध निर्माण पर जवाब उपाध्यक्ष से मांगने को कहते हैं, अब क्या छोटे–छोटे अवैध निर्माणों का जवाब समाचार संकलन के लिए उपाध्यक्ष महोदय से लिया जाए। आज हम बात करेंगे बाजार खाला क्षेत्र में चल रहे पांच अवैध निर्माण पर प्रवर्तन जोन–7 के बाजार खाला क्षेत्र बिल्लौचपुरा लोहा मंडी फाटक में चल रहे अवैध निर्माण की शिकायत 13.6.2023 को जोनल अधिकारी से की गई। जिसके बाद अवर अभियंता विपिन कुमार राय ने बिल्डर को सलाह दी की जल्द से जल्द निर्माण को बाहर से कंप्लीट कराके पेंट कर दे। बिल्डर ने अवर अभियंता का आदेश का अक्षरशः पालन करते हुऐ, इमारत को बाहर से पेंट करवा दिया है। निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर जोरों शोरों पर काम चल रहा है। अवर अभियंता उक्त बिल्डिंग को शीघ्र अध्यासित करवा देंगे, इस तरह का कार्य अपनी पूर्व तैनाती स्थतलों करवाने के लिए चर्चित रहें हैं।

आम महोत्सव में आम पर होगया सेमिनार

संवाददाता

लखनऊ। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक डॉ आर के तोमर ने बताया कि अवैध शिल्प ग्राम में 14से 16जुलाई तक आयोजित किए जा रहे "उ0प्र0 आम महोत्सव–2023 में तीन दिवसीय बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण की गोष्ठी का भी आयोजन होगा। पहला दिन विपणन और निर्यात पर दूसरा दिन खेती के नवाचारों और जैविक खेती पर, तथा तीसरे दिन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से सम्बन्धित संगोष्ठी का आयोजन होगा, जिसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।

तोमर ने आम महोत्सव के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आम महोत्सव के आयोजन से आम की विभिन्न किस्मों को प्रजातीय संरक्षण मिलेगा तथा आम के बागवानों में उन्नत एंव रंगीन किस्मों के प्रति रूझान बढ़ाने तथा गुणवत्तायुक्त उत्पादन तकनीकी हस्तान्तरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ–साथ जनमानस द्वारा आम की विविधता को देखकर ज्ञानार्जन के साथ–साथ हार्टी टूरिज्म के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।

बताया कि आम महोत्सव में आम की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया जायेगा, जिसमें राज्यों के आम उत्पादकों को अपनी आम की विभिन्न किस्मों को प्रदर्शनी में लाने के लिए प्रोत्साहित होंगें।

प्रदेश की प्रमुख व्यवसायिक आम की किस्मों के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट एवं गौण आम की किस्मों को प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसमें उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा संरक्षित एवं केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, द्वारा संरक्षित विकसित नवीनतम प्रजातियों तथा बागवानों द्वारा विभिन्न प्रजातियों को इस अवसर पर प्रदर्शित किया जायेगा।

एसएसपी ने कैंट थाना परिसर का किया औचक निरीक्षण, मिली खामियां

सावन माह में पुलिस कर्मी बरतें विशेष सुरक्षा - एसएसपी

अयोध्या।थाना कैंट परिसर में खामियां मिलने के चलते एसएसपी राज करण नैय्यर ने कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक के के मिश्र को जमकर खरी–खोटी सुनाई। उन्होंने मंगलवार की शाम कैंट थाना परिसर का औचक निरीक्षण किया।इस मौके पर उन्होंने वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ बैठक किया। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट के के मिश्र व अन्य पुलिस कर्मियों से कहा कि सावन माह में सभी शिवालयों व शिव मंदिरों पर विशेष ध्यान रखें।एसएसपी राज करण नैय्यर ने सबसे पहले जब थाना परिसर में प्रवेश किया तो वहां पर अजीबो गरीब ढंग से विभिन्न मामलों मे बंद दो पहिया व चार पहिया वाहन खड़े दिखाई दिये।जिसके चलते उन्होंने इसे सही तरीके से खड़ी करने का निर्देश प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट को दिये।इसके अलावा एसएसपी राज करण नैय्यर ने थाने के सभी अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया और उसमें कमियां मिलने पर संबंधित कर्मियों को दूर करने का निर्देश दिया।इसके बाद उन्होंने थाना परिसर में स्थित कार्यालय,भोजनालय, बैरिक, महिला हेल्प डेस्क आदि का निरीक्षण किया।जहां परद उन्होंने वहां पर सभी अभिलेखों के रख–रखाव व साफ–सफाई के संबन्ध में वहां पर संबंधित पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद उन्होंने वहां पर श्रावण मासध्कावड़ यात्रा व आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने के लिये वहां पर मौजूद प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट के के मिश्र व सभी पुलिस कर्मियों को दिया।बैठक में उन्होंने कहा कि सभी पुलिस कर्मी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सभी शिवालयों व शिव मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था मे कोई कोताही न बरतें।खासकर सावन के सोमवार को इन मंदिरों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रखी जाये।उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया कि कांवड़ियों व शिवभक्तों को सावन माह में कोई कष्ट न हो।इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक के के मिश्र के अलावा सभी पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

शिक्षक प्रकोष्ठ की बैठक हुई संपन्न

महाराजगंज। जिला मुख्यालय महाराजगंज में कांग्रेस पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला कार्यकारिणी एव प्रदेश पदाधिकारियों की पूर्व निर्धारित बैठक अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी शरद कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,जिसमें अजय कुमार सिंह चेयरमैन, उ प्र कांग्रेस कमेटी शिक्षक प्रकोष्ठ मुख्य अतिथि, शिव पाण्डेय कोषाध्यक्ष उ प्र कांग्रेस कमेटी प्रमुख अतिथि, एव आलोक प्रसाद चेयरमैन अनुसूचित प्रकोष्ठ उ० प्र० कांग्रेस,डॉ प्रमोद कुमार सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, रामनिवास चौबे सचिव उ प्र कांग्रेस कमेटी (शिक्षक प्रकोष्ठ) विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में , उ०प्र० कांग्रेस कमेटी शिक्षक प्रकोष्ठ चेयरमैन अजय कुमार सिंह की अनुमति से जिला पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों को शिक्षक प्रकोष्ठ, जिलाध्यक्ष अरविन्द कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। उक्त अवसर पर श्री अजय कुमार सिंह जी ने शिक्षक बंधुओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार चाणक्य जी ने अपने गुरुत्तर दायित्व का निर्वहन करते हुए जन विरोधी शासक नन्दवंश को सत्ता से उतार कर एक सुयोग्य शासक चन्द्रगुप्त मौर्य को स्थापित किया ठीक उसी प्रकार वर्तमान शिक्षक बंधुओं का कर्तव्य है कि भयंकर मॅहगाई, बेरोजगारी, के लिए उत्तरदायी किसान विरोधी,कर्मचारी विरोधी,निरंकुश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए पूर्ण मनोयोग से , राष्ट्र के भविष्य निर्माता युवाओं को दिशानिर्देशित करें , प्रेरित करें।

उक्त अवसर पर उपस्थित प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिलाकार्यरिणी के पदाधिकारी, तथा सैकड़ों शिक्षकों ने कर्तव्य पालन का संकल्प लिया।

भोजपुरी फिल्म तुमसे मिलने की तमन्ना हैं का शुभ मुहूर्त मुंबई में हुआ संपन्न,फिर दिखेगी सत्येंद्र-तनुश्री की सुपरहिट जोड़ी

मनोरंजन सिद्धि एंटरटेनमेंट वर्ल्डष के बैनर तले व निर्माता नंदलाल आर पांडे द्वारा निर्मित भोजपुरी फिल्म ष्तुमसे मिलने की तमन्ना हैं ष का शुभ मुहूर्त कल शाम मुंबई मायानगरी में सम्पन्न हुआ! इस खास मौके पर फिल्म के निर्माता नंदलाल आर पांडे,निर्देशक रुस्तम अली चिश्ती,अभिनेत्री पूजा सिंह,पूनम राय,सिंगर ममता उपाध्याय आदि उपस्थित रहीं! तथा सभी ने फिल्म के सफलता के लिए कामना की साथ ही साथ निर्माता नंदलाल आर पांडे को नए फिल्म के लिए बधाईयाँ दी! फिल्म में आपको एक्शन स्टार सत्येंद्र सिंह के साथ स्टार अभिनेत्री तनुश्री जोड़ी बनाती नजर आएंगी! जो दर्शकों एक बार फिर रोमांचित करेगी! ये फिल्म सम्पूर्ण पारिवारिक,सामाजिक व बाप बेटे के एक अनमोल रिश्ते पर आधारित फिल्म हैं! तथा फिल्म में आपको लव,एक्शन,रोमांस,कॉमेडी आदि सब एक साथ देखने को मिलेगा। जिससे दर्शक सिनेमाघरों में खिंचे चले आएंगे!

इस खास अवसर पर फिल्म के निर्माता नंदलाल आर पांडे ने बताया की ष्तुमसे मिलने की तमन्ना हैं ष फिल्म एक बेहतरीन पारिवारिक व सामाजिक फिल्म है! जिसका निर्माण कार्य काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी बनारस के रमणीय स्थलों पर शुरू हो जायेगा! हम इस फिल्म के माध्यम से भोजपुरी सिनेमा में फिर से पहले की तरह पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों का चलन शुरू करना चाहते हैं तथा इस फिल्म के जरिये बाप बेटे के खट्टी मीठी रिश्तों को बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हैं! फिल्म में आपको अभिनेता सत्येंद्र सिंह एक नये अवतार में नजर आयेंगे,जिसमें एक बेटे का मिला जुला किरदार देखने को मिलेगा! जिसको देख दर्शकों की आंखे नम हो जायेंगी! बेटे के किरदार में अभिनेता सत्येंद्र सिंह नजर आयेंगे तो वहीं बाप के किरदार को फिलहाल गुप्त रखा गया हैं! बात करें फिल्म की निर्माण की तो ये फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म हैं,जिसमें भोजपुरी सिनेमा के तमाम बड़े नाम अभिनय करते नजर आयेंगे!

ये फिल्म ष्सिद्धि एंटरटेनमेंट वर्ल्डष के बैनर तले बन रही है! फिल्म में आपको स्टार अभिनेता सत्येंद्र सिंह के साथ सुपरस्टार अभिनेत्री तनुश्री नजर आयेंगी साथ ही साथ आशीष सिंह बंटी,अभिनेत्री पूजा सिंह,कॉमेडी किंग् सीपी भट्ट,दिग्गज,सिने स्टार अनूप अरोड़ा,जीतू शुक्ला,अमित शुक्ला,अमित मिश्रा,जे पी सिंह,पूनम राय,संजू सोलंकी आदि प्रमुख हैं! फिल्म का निर्देशन बेहतरीन निर्देशकों में शूमार निर्देशक रुस्तम अली चिश्ती कर रहे है तथा फिल्म के प्रोड्यूसर नंदलाल आर पांडे व को–प्रोड्यूसर चंदा पांडे हैं। संगीत अनुज तिवारी का है,गीत ममता उपाध्याय का,गीतकार सोनू शर्मा व पवन मिश्रा हैं,डीओपी प्रमोद पांडे,सह निर्देशक अभिषेक सम्राट है! बात करें अभिनेता सत्येंद्र सिंह की तो ये निर्माता नंदलाल आर पांडे की बैक टू बैक दूसरी फिल्म हैं! इससे पहले सत्येंद्र निर्माता नंदलाल आर पांडे की फिल्म मामा भांजा कर चुके हैं! जिसका पोस्टर हाल ही में रिलीज हुआ था!

विशेष संवाददाता जय प्रकाश तिवारी

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक संपन्न

उमाकान्त लाला ब्यूरो चीफ

शाहजहाँपुर। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक सम्पन्न हुई । बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने एजेंडा के बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होने उद्यमियों की शिकायतों एवं सुझावों को भी सुना।

बनतारा एवं अट्सलिया के बीच विद्युत घर की स्वीकृति के संबंध में अधिशासी अभियंता विद्युत को प्रबंध निदेशक माध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लखनऊ को टेंडर निर्गत किए जाने के संबंध में अर्ध शासकीय पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था ।जिसके संबंध में निरंतर विलंब होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उपायुक्त उद्योग एवं अधिशासी अभियंता विद्युत से जवाब तलब करने के निर्देश दिये। अजीजपुर जिगनेरा में बने 220 केवी विद्युत सब स्टेशन को जमौर विद्युत सब स्टेशन से जोड़े जाने के संबंध में प्रबंध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लखनऊ को टेंडर निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में अर्ध शासकीय पत्र प्रेषित करने हेतु जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया। भूगर्भ जल स्रोत संरक्षण हेतु प्रत्येक भवन औद्योगिक परिसर जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर से अधिक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग रूफ टॉप स्थापना अनिवार्य कर दिए जाने पर सहायक अभियंता लघु सिंचाई को औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक संगठनों एवं पदाधिकारियों के मध्य रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित करने हेतु कैंप के आयोजन कराने के निर्देश दिए गए थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य में प्रगति ना पाए जाने पर जिलाधिकारी ने सहायक अभियंता लघु सिंचाई से जवाब तलब करने एवं अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के निर्देश दिए। औद्योगिक आस्थान रोजा में जल निकासी की समस्या को लेकर उद्यमियों ने जिलाधिकारी को जानकारी देने पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जल निगम के अधिकारियों को जल निकासी का प्रबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा , नगर मजिस्ट्रेट वेद प्रकश मिश्र , अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवम संबंधित अधिकारी व उद्यमी उपस्थित रहे।

विद्यालय में बालिकाओं का प्रवेश शुल्क शून्य रहेगा : शिक्षाविद अजय दुबे

संवाददाता

लखनऊ। कानपुर रोड स्थित मानसरोवर योजना में मंगलवार को द विद्यालय संस्कारों की पाठशाला प्ले ग्रुप स्कूल्स की चेन का उद्घाटन चेयरमैन हैदरगढ़ आलोक तिवारी, उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी तथा सुरेश चन्द्र तिवारी पूर्व एमडी उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग ने किया। इस मौके पर 11 शाखाओं का उद्घाटन वर्चुअल मोड में किया गया तथा हनुमान जी के विशाल भण्डारे का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने शिक्षाविद अजय दुबे को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि द विद्यालय नामचीन किड्स एजुकेशन संस्थानों को कड़ी चुनौती देगा क्योंकि यहां आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी आदान–प्रदान होगा। पिछले 15 वर्षों से लाखों नौजवानों को रोजगार की राह दिखा चुके बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक, शिक्षाविद अजय दुबे ने अब बचपन को भी संस्कारित करते हुए शिक्षित करने की ठान ली है। द विद्यालय संस्कारों की पाठशाला के नाम से प्ले ग्रुप स्कूल्स चेन की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिकता के साथ साथ पौराणिक शिक्षा पद्धति पर बच्चों को शुरू से ही संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाएगा। द विद्यालय में डे केयर, प्ले ग्रुप, नर्सरी और केजी कक्षाओं में आधुनिकतम तकनीक से लैस स्मार्ट क्लासेज होंगी तथा बालिकाओं का प्रवेश शुल्क शून्य रखा गया है। विद्यालय प्ले ग्रुप स्कूल्स चेन की शुरुआत करने की आवश्यकता का जवाब देते हुए मुख्य कार्यपालक अधिकारी अजय दुबे ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर केवल अक्षरों का ज्ञान या रटंत विद्या ही सम्पूर्ण शिक्षा नहीं है इसका अनुभव मैंने बड़े विद्यार्थियों को शिक्षित करते हुए किया। बचपन से बच्चों में आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कारों का प्रवाह हो जो राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध हो इसी मूल भावना से द विद्यालय कार्य करेगा। द विद्यालय के लोगो में दिख रही पांच कमल की पंखुड़ियां पंचतत्वों का प्रतीक है जो शैशवास्था और बाल्यावस्था को संस्कारों से पल्लवित पुष्पित करेगा। आगामी योजनाओं की जानकारी देते हुए श्री दुबे ने बताया कि 11 जुलाई को द विद्यालय की 11 शाखाओं का एक साथ उद्घाटन किया जाएगा और निरंतर गुणवत्ता बनाए रखते हुए देश भर में 100 शाखाएं का लक्ष्य मार्च 2024 तक पूरा करने के बाद 500 ब्रांचेस का विस्तार चौनल पार्टनर्स के साथ मिलकर किया जाएगा। इसके बाद पांचवीं कक्षा तक प्रत्येक शाखा के विस्तार की योजना बनाई गई है।

श्री जयनारायण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बी०बी०ए० (आई०बी०) षष्ठम सेमेस्टर की मौखिकी परीक्षा की तिथि तय

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। श्री जयनारायण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ के प्राचार्य प्रो० विनोद चन्द्रा ने बताया कि महाविद्यालय में बी०बी०ए० (आई०बी०) षष्ठम सेमेस्टर के छात्रों के टपअं–टवबम परीक्षा दिनांक 14.07.2023 को पूर्वान्ह 11:30 बजे से आयोजित की जायेगी। अधिक जानकारी के लिए छात्र, विजय राज श्रीवास्तव प्रभारी बी०बी०ए० (आई०बी०) विभाग से सम्पर्क कर सकते हैं।

महावीर मंदिर पटना की तरफ से राम लला भेंट किया गया दो करोड़ रुपए का चेक

(डॉ अजय तिवारी जिला संबाददाता)

09नवंबर 2019 को रामलला के पक्ष में फैसला आने के 1 घंटे के भीतर मंदिर निर्माण के निमित्त घ10 करोड का सहयोग देने की महावीर मंदिर पटना ने की थी घोषणा, महावीर मंदिर पटना की तरफ से रामलला को अब तक भेंट किया जा चुका है 8 करोड़ रुपए, रामलला के भव्य महल में विराजमान होने के समय भी महावीर मंदिर पटना रामलला को समर्पित करेगा दो करोड़ रुपए, महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपा 2 करोड रुपए का चौथा चेक।

इनरव्हील क्लब ऑफ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट 312 ने मंगलवार को शाइन ऑलाइट एवं शेयर की थीम के साथ अपने नये सत्र का आगाज किया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। इनरव्हील क्लब आफ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट 312 ने मंगलवार को शाइन अ लाइट एवं शेयर की थीम के साथ अपने नये सत्र का आगाज किया। निराला नगर स्थित एक होटल में इंस्टालेशन सेरेमनी में नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट मालविका गुप्ता, सेकेट्री शिखा राज,वाइस प्रेसिडेंट संगीता मित्तल एवं अन्य कार्यकारणी सदस्यों का इंस्टालेशन किया गया।इस अवसर पर मुख्य अतिथि एसोसिएशन मेम्बर डा वर्षा विनय कुमार एवं गेस्ट आफ आनर डिस्ट्रिक्ट एडीटर शिखा भार्गव उपस्थित थीं। मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के पश्चात् अनामिका और दीप्ति ने गणेश वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वर्षा जी ने मालविका गुप्ता और नमी टीम का उत्साह वर्धन किया।

शिखा भार्गव ने शाइन अ लाइट थीम पर प्रकाश डाला।अध्यक्षा चुने जाने पर सभी को धन्यवाद देते हुए मालविका गुप्ता ने क्लब के द्वारा किए गये सेवा कार्य एवं आने वाले प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी। बालिका मानवी की शिक्षा, वृद्धा को वाकिंग स्टिक, दो महीने के बच्चे को इलाज का खर्च, सिलाई मशीन और कपड़ा आदि सेवा कार्य किये गये।जीरो वेस्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सुशीला जी ने पूछा के फूलों से अगरबत्ती बनाना सिखाया।क्लब का न्यूज बुलेटिन भी रिलीज किया गया। कार्यक्रम में अन्य क्लब के सम्मानित सदस्य एवं वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। विपुला ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया।

तप हमारी चेतना को निखारता है.... आचार्य श्री

संवाददाता

लखनऊ। चारबाग जैन मंदिर में चातुर्मास कर रहे आचार्य श्री 108 विशद सागर जी महाराज ने मंगलवार को मंगल प्रवचन में कहा कि असली तप हर परिस्थिति में मन की प्रसन्नता को बनाये रखना है। तप हमारी चेतना को निखारता है। कटु शब्द को सुनकर नजरअंदाज करना भी एक तप है। सुबह में मन्दिर जी में प्रभु का अभिषेक, शांतिधारा, पूजन सम्पन्न हुआ। आचार्य विशद सागर ने प्रवचन के दौरान कहा कि जो धर्म की शरण आता है वह शीघ्र ही भव से पार हो जाता है। इस मौके पर आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज द्वारा ही रचित लघु प्रतिक्रर्मण पुस्तक का विमोचन सुनील जैन ने किया। उनके साथ में विकास जैन एवं पवन कुमार सेठी भी थे। यह पुस्तक एक पूजन की विधि है। इस मौके पर संजीव,विकास, सुनील जैन,प्रवेश जैन, दीपक जैन,माया जैन,अरुण प्रभा जैन सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद थे।

मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र में चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। यह चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का पहला अनुपूरक बजट होगा। मानसून सत्र की तारीख तो तय नही लेकिन जुलाई के आखिरी सप्ताह या अगस्त में हो सकता है। यह विधानमंडल का दूसरा सत्र होगा। योगी सरकार ने शीतकालीन सत्र में 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 6,90,242.43 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। योगी सरकार की कोशिश लोकसभा चुनाव को संज्ञान में रखते हुए होगी। केंद्र में फिर एनडीए की हुकूमत बने ,इसे ध्यान में रखकर आयेगा बजट,ऐसा अनुमान है। भाजपा के पक्ष में माहौल के लिए योगी सरकार विकास कार्यों को गति देने की कोशिश में है। सड़क, एक्सप्रेस वे, हवाई अड्डों और बिजली से जुड़ी परियोजनाओं को सरकार तेजी से पूरा करने में जुटी है। परियोजनाये सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा सकती है। बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए सरकार अनुपूरक बजट के माध्यम से संसाधनों का इंतजाम कर सकती है। वित्त विभाग की अनुपूरक बजट के लिए तैयारी शुरू है।सरकार भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है।

नसबंदी से दूर भाग रहे पुरुष, फैमिली प्लानिंग महिलाओं के भरोसे

संवाददाता

लखनऊ। परिवार नियोजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार जागरूकता अभियान चलाता है। इसकी जिम्मेदारी ज्यादातर आशा कार्यकर्ताओं को दी गई है। इस अभियान में हर साल करीब दो हजार कार्यकर्ता घर–घर जाकर जागरूक करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी काउंसलिंग की जाती है। इसका नतीजा जहां महिलाओं में सकारात्मक दिखता है, वहीं पुरुषों में इसका उलट है। इस वर्ष 2022–23 के आंकड़ों में स्वास्थ्य विभाग पिछले साल 2021–22 के भी आंकड़े को नहीं छू पाया है, हलांकि महिलाओं में नसबंदी कराने का आंकड़ा बढ़ा है, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत देने वाला है। इसको लेकर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज अग्रवाल का कहना है कि पुरुष नसबंदी के बाद किसी भी तरह की शारीरिक या यौन कमजोरी नहीं आती है। यह पूरी तरह सुरक्षित और आसान है। लेकिन अधिकांश पुरुष–अभी भी इसे अपनाने में हिचक रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं समुदाय में अभी भी पुरुष नसबंदी से संबंधित जानकारी का अभाव है।

वहीं, महिलाओं में नसबंदी की प्रक्रिया पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा जटिल होती है। इसके अलावा पुरुष नसबंदी से न तो शारीरिक कमजोरी आती है और न ही संक्रमण का डर रहता है। इसके लिए बहुत सामान्य सा आपरेशन है जिसमें आधे घंटे से भी कम का समय लगता है। यहा तक कि लाभार्थी को अस्पताल में रहने की जरूरत भी नहीं पड़ती तथा वह आपरेशन द्वारा के आधे घंटे के बाद अपने घर भी जा सकते हैं। उनमें किसी भी प्रकार के शारीरिक बदलाव या दिनचर्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही नसबंदी से भविष्य में किसी तरह की स्वास्थ्यजनित समस्या होती है। पुरुष नसबंदी को लेकर पुरुषों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है और यह समझना है कि परिवार नियोजन अकेले पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है। पुरुष नसबंदी परिवार नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा अपनाया जाने वाला एकमात्र स्थायी साधन है।

इसलिए यह जरूरी है कि नसबंदी के समय लाभार्थी की उम्र 22 वर्ष से कम या 60 वर्ष से ज्यादा नहीं हो। लाभार्थी शादीशुदा हो। लाभार्थी कम से कम एक बच्चे का पिता हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। आमतौर पर पुरुष सोचते हैं कि नसबंदी के बाद सेक्स में कमी आती है, जबकि उनका यह भी मानना है कि इससे वह शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं और मेहनत का काम नहीं कर सकते। सीएमओ मनोज मनोज अग्रवाल ने बताया कि पुरुषों में यह भ्रांति गलत है। नसबंदी से शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और नसबंदी करना आसान है।

हिन्दी सांध्य दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी प्रभुदयाल श्रीवास्तव की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0–7007415808,9628325542,9415034002

RNI संन्दर्भ संख्या – 24/234/2019/R-1

deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से सम्बन्धित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायलय होगा।